

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022

हाल ही में भारत ने अपने समग्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IIP) स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है और इसके परिणामस्वरूप भारत [अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक](#) में 55 देशों में से 43वें स्थान पर है।

- अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा संकलित एक वार्षिक रिपोर्ट है।
- इस वर्ष (2022) अमेरिका 95.4% के साथ इस सूचकांक में शीर्ष पर है।

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक:

- 2020 यूएस चैंबर 'अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक' जिसका शीर्षक 'आर्ट ऑफ द पॉसबिल' है, उन अर्थव्यवस्थाओं के लिये एक खाका तैयार करता है जो अधिक प्रभावी बौद्धिक संपदा सुरक्षा के माध्यम से 21वीं सदी ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखते हैं।
 - अपने आठवें संस्करण में सूचकांक 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा पारस्थितिकी तंत्र का मानचित्रण करता है, जो वैश्विक [सकल घरेलू उत्पाद](#) के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
 - सूचकांक 50 से अधिक अद्वितीय संकेतकों के साथ प्रत्येक उस अर्थव्यवस्था के लिये बौद्धिक संपदा ढाँचे का मूल्यांकन करता है जो सबसे प्रभावी बौद्धिक संपदा प्रणालियों के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ये संकेतक किसी अर्थव्यवस्था के समग्र आईपी पारस्थितिकी तंत्र का एक ढाँचा तैयार करते हुए सुरक्षा की नौ श्रेणियाँ प्रदान करते हैं-
 - पेटेंट (Patents)
 - कॉपीराइट (Copyrights)
 - ट्रेडमार्क (Trademarks)
 - डिज़ाइन का अधिकार (Design Rights)
 - व्यापार में गोपनीयता (Trade Secrets)
 - आईपी संपत्तियों का व्यावसायीकरण (Commercialization of IP Assets)
 - प्रवर्तन (Enforcement)
 - सर्वांगी दक्षता (Systemic Efficiency)
 - सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन (Membership and Ratification of International Treaties)

यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स

- यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापार संघ है जो आकार, क्षेत्रों तथा क्षेत्रों के साथ-साथ राज्य एवं स्थानीय कक्षाओं व उद्योग संघों के 3 मिलियन से अधिक व्यवसायों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
- इस समूह की स्थापना अप्रैल 1912 में राष्ट्रपति विलियम हॉवरड टैफ्ट और उनके वाणिज्य एवं श्रम सचिव 'चार्ल्स नागेल' के आग्रह पर स्थानीय वाणिज्य मंडलों के माध्यम से की गई थी।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संरक्षण हेतु भारत सरकार की पहलें

- भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति 2016
- भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) का भी सदस्य है, जो काआईपीआर से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों को प्रशासित करता है।

स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड

